भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1888
उत्तर देने की तारीख 11 फरवरी, 2026

भारत में उपग्रह आधारित सेवाएं

1888. श्री बैजयंत पांडाः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में उन्नत उपग्रह-आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है या विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा उपग्रह-आधारित संचार सेवाओं को वहनीय बनाए रखने और विशेषकर ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल असमानता को कम करने में सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एवं ऑथराइजेशन सेंटर (इन-स्पेस) के "भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए दशकीय विजन और रणनीति" के अनुसार 2033 तक उपग्रह संचार सेगमेंट की अनुमानित बाजार संभावना 14.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

दूरसंचार विभाग के उपग्रह संचार सुधार-2022 ने ईज़ आफ डुईंग बिजनेस को सुगम बनाया है, कई प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है और विभिन्न शुल्कों को युक्तिसंगत बनाया है। हाल ही में हुए अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से गैर-सरकारी संस्थाओं को उपग्रह-आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए उपग्रह प्रणालियों के निर्माण/पट्टे पर देने, स्वामित्व और संचालन करने की ज़्यादा भागीदारी मिल सकेगी। कई ऑपरेटरों ने भारत भर में उपग्रह संचार प्रदान करने के प्राधिकार के लिए आवेदन किया है।

उपग्रह आधारित संचार सेवाएं ग्रामीण, दूरस्थ, अल्प-सेवा वाले और सेवा से वंचित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान कर सकती हैं, जिन्हें अन्यथा ऑप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेव आदि जैसे स्थलीय मीडिया के माध्यम से कवर करना मुश्किल है। यह डिजिटल असमानता को पाटने और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने में सहायता करेगा।

इसके अलावा, यह परिकल्पित है कि उपग्रह आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिक लाइसेंसधारकों के साथ इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से सेवाएं वहनीय होंगी।

*****